भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1978

दिनांक 29 नवम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केन्द्रों में संग्रहित डाटा का डिजिटलीकरण

1978. श्री दुष्यंत सिंहः

डॉ. संजय जायसवालः

श्रीमती अपराजिता सारंगीः

श्री कार्ती पी॰ चिदम्बरमः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर के आंगनवाड़ी केन्द्रों से संग्रहित किए डाटा का डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने हेतु कोई रूपरेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस डाटा का डिजिटलीकरण कब तक होने की संभावना है;

(ग) डिजिटलीकरण प्रक्रिया की स्थिति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रक्रिया की पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु क्या तंत्र और रणनीति अपनाई गई है; और

(ङ) आंगनवाड़ी केन्द्रों में साक्षरता-दर और गणन-कौशल में सुधार करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या पहलें की गई हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी   महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग) : आंगनवाड़ी सेवा में मासिक, तिमाही और छमाही आधार पर नियमित रिपोर्टों के माध्यम से मानकीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से विभिन्न इनपुट प्रक्रिया, आउटपुट तथा प्रभाव संकेतकों के संबंध में स्कीम की भौतिक प्रगति का जायजा लेने के लिए शुरुआत से ही एक अंतरनिर्मित निगरानी तंत्र है। आंगनवाड़ी सेवा स्कीम की निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों का डाटा ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु आईसीडीएस-त्वरित रिपोर्टिंग प्रणाली (आरआरएस) नामक संशोधित एमआईएस भी शुरू किया गया है। आईसीडीएस-आरआरएस के अंतर्गत प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र को 11 डिजिट का एक विशिष्ट कोड तथा लॉगइन पासवर्ड पर्यवेक्षक स्तर पर आबंटित किया जाता है ताकि वे मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। अब तक 1377595 आंगनवाड़ी केंद्रों में से 1370927

आंगनवाड़ी केंद्रों को 11 डिजिट का विशिष्ट कोड आवंटित किया जा चुका है। ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक I में उपलब्ध है जिन्हें 11 डिजिट का विशिष्ट कोड आवंटित किया गया है।

इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण अभियान के अंतर्गत आईसीडीएस-सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (आईसीडीएस-सीएएस) की शुरुआत के साथ भौतिक रजिस्टरों का डिजिटीकरण शुरू किया गया है। आईसीडीएस-सीएएस का मोबाइल आधारित सॉफ्टवेयर विकास चार्ट की ऑटो प्लाटिंग के आधार पर अल्पवजनी बच्चों की पहचान को संभव बनाता है। राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध ड्रिल-डाउन डैशबोर्ड पोषण की समस्या की पहचान करने और दूर करने में योगदान करता है।

25 नवम्बर 2019 की स्थिति के अनुसार 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 543863 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां आईसीडीएस-सीएएस एप्लीकेशन का प्रयोग कर रही हैं। राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक II में दिया गया है।

(घ) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजना को लागू करने के तंत्र में विडियो कन्फ्रेंस, बैठकों के माध्यम से नियमित समीक्षा तथा अधिकारियों द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा शामिल है।

(ड़) : आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के अंतर्गत बच्चों (3-6 वर्ष) को अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा सेवा प्रदान की जाती है। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रति आंगनवाड़ी केंद्र प्रति वर्ष 5 हजार रुपये की दर से निधियां प्रदान की जाती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अपने आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के साक्षरता और संख्यात्मक कौशल में सुधार ला सकें।

****

अनुलग्नक -I

आंगनवाड़ी केन्द्रों में डाटा संग्रह का डिजिटाइजेशन विषय पर श्री दुष्यंत सिंह, डॉ. संजय जायसवाल, श्रीमती अपराजिता सारंगी और श्री कार्ति पी. चिदम्बरम द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1978 का लोक सभा में दिनांक 29.11.2019 को दिए जाने वाले उत्तर के भाग (ग) में संदर्भित अनुलग्नक का विवरण

आईसीडीएस – आरआरएस पर 11 अंकों का विशिष्ट कोड वाले आंगनवाड़ी केंद्रों की राज्यवार स्थिति

क्र.सं	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या		
		अनुमोदित	क्रियाशील	11 अंकों का विशिष्ट कोड सौंपे गए केन्द्र
1	अंडमान एवं निकोार द्वीप	720	720	717
2	आंध्र प्रदेश	55607	55607	55531
3	अरुणाचल प्रदेश	6225	6225	6163
4	असम	62153	62153	61724
5	बिहार	115009	104090	104090
6	चंडीगढ़	450	450	450
7	छत्तीसगढ़	52474	51301	51301
8	दादरा एवं नागर हेवली	302	302	302
9	दमन एवं दीव	107	107	102
10	दिल्ली	10897	10897	10897
11	गोवा	1262	1262	1262
12	गुजरात	53029	53029	53029
13	हरियाणा	25962	25962	25962
14	हिमाचल प्रदेश	18925	18925	18925
15	जम्मू एवं कश्मीर	30765	28459	28747
16	लद्दाख	1173	1140	
17	झारखंड	38432	38432	38432
18	कर्नाटक	65911	65911	65911
19	केरल	33318	33244	33146
20	लक्षद्वीप	107	107	107
21	मध्य प्रदेश	97135	97135	97135
22	महाराष्ट्र	110486	110219	109708
23	मणिपुर	11510	11510	11510
24	मेघालय	5896	5896	5896
25	मिजोरम	2244	2244	2244

26	नगालैंड	3980	3980	0
27	ओडिशा	74154	72587	72587
28	पुद्दुचेरी	855	855	855
29	पंजाब	27314	27289	27289
30	राजस्थान	62010	61974	61348
31	सिक्किम	1308	1308	1308
32	तमिलनाडु	54439	54439	54439
33	तेलंगाना	35700	35634	35634
34	त्रिपुरा	10145	9911	9885
35	उत्तर प्रदेश	190145	187997	187997
36	उत्तराखंड	20067	20067	20067
37	पश्चिम बंगाल	119481	116227	116227
	कुल	**13,99,697**	**13,77,595**	**13,70,927**

<u>अनुलग्नक -II</u>

आंगनवाड़ी केन्द्रों में डाटा संग्रह का डिजिटाइजेशन विषय पर श्री दुष्यंत सिंह, डॉ. संजय जायसवाल, श्रीमती अपराजिता सारंगी और श्री कार्ति पी. चिदम्बरम द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1978 का लोक सभा में दिनांक 29.11.2019 को दिए जाने वाले उत्तर के भाग (ग) में संदर्भित अनुलग्नक का विवरण

आईसीडीएस – आरआरएस एप्लिकेशन का प्रयोग करने वाले आंगनवाड़ियों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	आईसीडीएस – आरआरएस एप्लिकेशन का प्रयोग करने वाले केन्द्रों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	714
2.	आंध्र प्रदेश	55,586
3.	असम	8,635
4.	बिहार	56,648
5.	चंडीगढ़	450
6.	छत्तीसगढ़	10,473
7.	दादरा एवं नगर हवेली	303
8.	दमन एवं दीव	102
9.	दिल्ली	9,386
10.	गोवा	968
11.	गुजरात	52,932
12.	हिमाचल प्रदेश	18,864
13.	झारखंड	11,127
14.	केरल	10,156
15.	लक्षद्वीप	1
16.	मध्य प्रदेश	27,811
17.	महाराष्ट्र	1,09,621
18.	मेघालय	5,813
19.	मिजोरम	2,244
20.	नगालैंड	3,674
21.	पुद्दुचेरी	848
22.	राजस्थान	20,758
23.	सिक्किम	821
24.	तमिलनाडु	5,4401
25.	तेलंगाना	11,157
26.	उत्तर प्रदेश	51,797
27.	उत्तराखंड	18,573
कुल		**5,43,863**

(25 नवंबर, 2019 तक)